



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2813 /2026

मनोहर लाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

: हिमांशु मिश्रा

प्रतिवादी अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. सिंह को सुना और रिकॉर्ड देखा।
3. आवेदक मामला अपराध संख्या 556/2025, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 103(1), 125 बीएनएस, पुलिस स्टेशन जैत, जिला मथुरा के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि इसी तरह के सह-आरोपी विकास को इस कोर्ट ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 45058/2025 में 9.1.2026 को पास किए गए आदेश के ज़रिए पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी जैसी ही है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आवेदक 5.1.2026 से जेल में बंद है और उसका एक मामले में आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसके बारे में बताया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. बेल की अर्जी का राज्य विधि अधिकारी ने ज़ोरदार विरोध किया है। हालांकि, सह-आरोपी के साथ समानता के ऊपर बताए गए तथ्य पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है।

6. सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम यूपी राज्य और अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** में कहा है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामला का लंबित होना ही जमानत देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता, अगर किसी और वजह से उसकी जमानत का मामला बनता है।

7. मामले के तथ्यों और हालात को देखते हुए और इस न्यायालय के **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 सीआरएल.एल.जे. 938** में दिए गए फैसले और सर्वोच्च न्यायालय के **पारस राम विश्रोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 825**, में दिए गए फैसलों को देखते हुए, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। समानता के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

8. आवेदक- **मनोहर लाल**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है।

(i) आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने उन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा जो (1) मामला शुरू करने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई हैं। अगर विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की गैरहाज़िरी जानबूझकर या बिना किसी सही वजह के है, तो विचारण न्यायालय को इस तरह की गलती को जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मानने और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोग पक्ष को इस न्यायालय में जमानत रद्द करने का आवेदन देने की आज़ादी होगी।

10. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और रहने का सबूत संबंधित न्यायालय से सत्यापित किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

28 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।